युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए ₹1225 करोड़

राज्य सरकार ने 1.25 लाख युवा उद्यमी बनाने का रखा लक्ष्य

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का अहम योगदान है। शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए उद्योगों के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया गया है। बजट में इसके 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं से 1.25 लाख नए उद्यमी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।

बजट में हथकरघा उद्योग पर भी खास फोकस किया गया है। कृषि क्षेत्र के बाद प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर हैं। प्रदेश में 2.58 लाख पावरलूम हैं जिसके माध्यम से लगभग 5.50 लाख पावरलूम बुनकर अपना

जीविकोपार्जन कर रहे हैं। उनके लिए उप्र. वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के क्रियान्वयन के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वर्ष 2025-2026 में ब्याज उपादान मद में समुचित व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके तहत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जिससे स्थापित होने वाले नए उद्यमों के माध्यम से 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के लिए 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऐसे ही उप्र. माटी कला बोर्ड के संचालन के लिए 11.50 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

निवेश मित्र ने बनाया रिकॉर्ड

निवेश मित्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-2025 में नवंबर 2024 तक 6,62,672 उद्यम पंजीकृत हुए, जिसमें 59,64,048 लोगों को रोजगार मिला। इस तरह करीब 96 लाख एमएसएमई इकाइयों की संख्या और 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ यूपी देश भर में सबसे आगे है।